

भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना के संबंध में अनश्चितता

[स्रोत: द हट्टि](#)

हाल ही में [जनगणना](#) के लिये प्रशासनिक सीमाएँ तय करने की समय-सीमा समाप्त हो गई, लेकिन नई तथिकी घोषणा नहीं की गई। इस प्रकार जनगणना की प्रक्रिया के समय को लेकर अनश्चितता बनी हुई है।

भारत में जनगणना कार्य के संबंध में नवीनतम अपडेट क्या हैं?

- **समय-सीमा वसितार:** जनगणना के लिये आवश्यक प्रशासनिक सीमाओं को निर्धारित करने की समयसीमा दिसंबर 2020 से नौ बार बढ़ाई जा चुकी है।
- **हाल के वसितार का प्रभाव:**
 - **जनगणना समयरेखा पर:**
 - इस वसितार से जनगणना की शुरुआत कम-से-कम 1 अक्टूबर, 2024 तक स्थगित हो गई है, क्योंकि इस कार्य के लिये गणनाकर्त्ताओं को तैयार करने में आमतौर पर तीन महीने लगते हैं। स्पष्टता की यह कमी जनगणना कार्यक्रम को लेकर अनश्चितता को बढ़ाती है।
 - **महिला आरक्षण अधिनियम पर:**
 - **महिला आरक्षण** का कार्यान्वयन, जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित हैं, जनगणना तथा उसके बाद होने वाले **परसिमन** कार्य के पूरा होने पर निर्भर करता है।
 - आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना के आँकड़ों के आधार पर परसिमन आवश्यक है।
- **अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना:**
 - कुछ राजनीतिक दलों ने आगामी जनगणना प्रक्रिया में **जातिजनगणना** को शामिल करने की मांग की है। यह मांग भारतीय समाज में सामाजिक वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व पर व्यापक चर्चा को रेखांकित करती है।

DECENNIAL POPULATION CENSUS



A process of collecting, compiling, analysing and disseminating demographic, economic and social data (at a specific time) of all persons in a country.

BRIEF HISTORY

- Earliest mentions: **Rigveda** (800-600 BC), **Arthashastra** (300 BC) & **Ain-i-Akbari** (16th century)
- 1st Non-synchronous Census (held in a few places): **1872** under **Gov. Gen. Lord Mayo**
- 1st Synchronous Census (held all over British India): **1881** by **W.C. Plowden** (Census Commissioner of India) under **Lord Ripon**

RESPONSIBLE BODY

- Until 1951, Census Organisation was set up on an ad-hoc basis for each Census
- Since 1951, Office of the **Registrar General and Census Commissioner** (MHA)

LEGAL BACKING

- A Union list subject under **Article 246**
- Conducted under **Census Act (CA), 1948**

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION COLLECTED

- Guaranteed under CA 1948
- Information not even accessible to the courts of law

SIGNIFICANCE

- Largest single source of statistical information about people of India
- Used for good governance purposes
- Demarcation of constituencies & representation in Legislature

Census	Major Event
5 th (1921)	Only census to witness a decadal population decline (0.31%) Hence, called the year of " The Great Divide "
11 th (1971)	Added information on fertility for currently married women
13 th (1991)	Concept of literacy changed to children aged 7+ (previously 4+)
14 th (2001)	Leap in tech front; usage of Intelligent Character Reading (ICR)
15 th (2011)	Notable fall in case of Empowered Action Group (EAG) States noticed first time

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

ABOUT

- Conducted in **2011** for the **first time since 1931**

COMPONENTS

- Economic status** (to define a poor/deprived person)
- Specific caste** (to evaluate caste groups that are economically worse/better off)

CONSTITUTIONAL BACKING

- Article 340** mandates the **appointment of a commission** to investigate the conditions of socially/educationally backward classes

Census v/s SECC

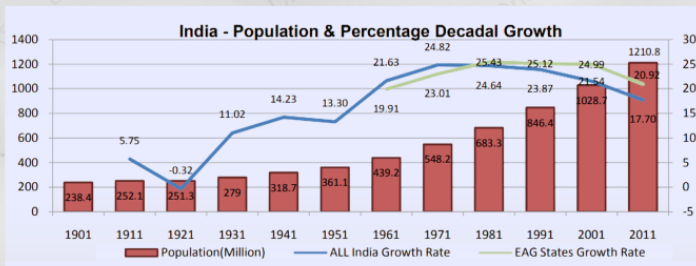
- SECC **identifies beneficiaries** of state support (Census - national population data)
- SECC **data open for use** by govt depts (Census data - confidential)

SIGNIFICANCE

- Better inequality mapping
- Quantifiable data to support existing reservation levels

SOME KEY FINDINGS OF SECC 2011

- Total Households - 24.49 crore
 - Rural - 17.97 crore
 - SC/ST Households - 3.87 crore (21.56%)
- Households with no literate adult (age >25) - 23.5%



जनगणना क्या है?

- ऐतिहासिक संदर्भ और आवृत्ति:
 - भारत की पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू. सी. प्लोडेन के नेतृत्व में हुई थी। तब से यह बिना किसी रुकावट के हर दशक में आयोजित की जाती रही है।
 - यद्यपि भारत की जनगणना अधिनियम, 1948 कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन यह अनिवार्य आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं करता।
 - दशकीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता के बजाय एक परंपरा है।
 - गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, इस दशकीय गणना कार्य के संचालन की ज़िम्मेदारी देखता है।
- उद्देश्य:
 - जनगणना देश की जनसंख्या का एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराती है, जो प्रगति की समीक्षा, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन तथा भावी पहलों की योजना बनाने के लिये आधार का काम करती है।
- प्रवधि: गणना दो मुख्य चरणों में की जाती है:
 - मकान सूचीकरण तथा मकान गणना (Houselisting/Housing Census): इस प्रारंभिक चरण में देश की सभी अवसंरचनाओं का विवरण दर्ज किया जाता है, जिसमें उनके प्रकार, उपलब्ध सुविधाएँ और मौजूदा परसिंपत्तियाँ शामिल हैं।
 - जनसंख्या गणना: यह अधिक व्यापक चरण देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी राष्ट्रीयता भारतीय से भिन्न हो, के बारे में वसित्त जानकारी एकत्र करता है।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
 - भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के गणना के लिये एक ही प्रकार के 10-वर्षीय चक्र का पालन किया जाता है जबकि स्वीट्ज़रलैंड, कनाडा और जापान जैसे कुछ देश प्रत्येक पाँच वर्ष में गणना करते हैं।

जनगणना डेटा 2011

- जनसंख्या: वर्ष 2011 में 17.7% की वृद्धि के साथ जनसंख्या 1.21 बिलियन हो गई, जिसमें महिलाओं की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि से अधिक रही।
- साक्षरता: साक्षरता दर बढ़कर 73% हुई, जिसमें महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में अधिक रही।
- जनसंख्या घनत्व: जनसंख्या घनत्व बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ।
- लिंग अनुपात: सुधार के साथ यह 940 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हुआ।
- धार्मिक जनसांख्यिकी: 79.8% जनसंख्या हिंदू तथा मुस्लिम जनसंख्या 14.23%।
- नई श्रेणी: इसमें एक "कोई धर्म नहीं" नामक विकल्प पेश किया गया, जिसका चयन 0.24% लोगों ने किया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर (घातीय) तीन गुना हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. सरकार की दो समानांतर चलाई जा रही योजनाएँ, यथा 'आधार कार्ड' और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एन.पी.आर.), एक स्वैच्छिक तथा दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों एवं मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिये कि क्या दोनों

योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है? इन योजनाओं को वकिसात्मक लाभों और न्यायोचति संवृद्धि प्राप्त करने की संभाव्यता का वशिलेषण कीजयि। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/uncertainty-regarding-india-s-next-national-census>

